

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 54/19

GCMS NO 2019/00161

1. भँवर सिंह पुत्र विशन सिंह
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र विशन सिंह
3. फूलदेई पत्नि रघुपत सिंह
4. हनुमान सिंह
5. धारा सिंह पुत्रान रघुपत सिंह

उदय सिंह पुत्र प्रेम सिंह समस्त जातियान राजपूत निवासीयान माधोपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांत

बनाम

1. बल्लू सिंह
2. किशन सिंह
3. दशरथ सिंह
4. राजेन्द सिंह
5. सुमेर सिंह पुत्रान जगमान सिंह
6. गिरजा देवी पत्नि दशरथ सिंह
7. लाडकंवर पत्नि सुमेर सिंह जातियान राजपूत निवासीयान माधोराजपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
8. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली
9. तहसीलदार टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 05/19 निर्णय दिनांक 6.11.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम)
अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम शर्मा
अभिभाषक रेस्पो0 श्री सुरेश चंद शर्मा

दिनांक 05.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 6.11.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम माधोपुरा स्थित आराजी खसरा न0 152 रकबा 0.35 है9, 151 रकबा 0.58 है0, अन्य आवेदकगण के नाम है। आराजी खसरा न0 151 व 152 के पूर्व की ओर आवेदक की खातेदारी की भूमि खसरा न0 153,154,155 है तथा खसरा न0 151, 152 के पश्चिम की ओर खसरा न0 135 रकबा 0.19 है0 गैर मुमकिन रास्ता है। आवेदकगण हमेशा से अपनी आराजी खसरा न0 154, 155 में रास्ता खसरा न0 135 से खसरा न0 152, 153 की दक्षिण दिशा की ओर डोल में होकर निकल रहे हैं इसी में होकर आवेदकगण के पहले बैलगाड़ी


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

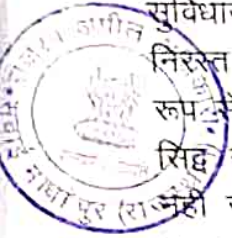
तथा अब फसल को बोन के लिए टेक्टर लाने लेजाने व पशुधन का लाने ले जाने के काम मे लेते चले आ रहे है। उक्त रास्ता मुख्य रास्ते खसरा न0 135 से 10 फीट चौडा और करीब 60 फीट लम्बा है। उसके बाद आवेदक की आराजी जो कय शुदा है खसरा न0 153 है। खसरा न0 154 व 155 आवेदकगण की आराजी है। आवेदकगण की आराजी पर पहुँच का एक मात्र मार्ग यही है। जिसे आवेदकगण बिना रोकटोक के बजाने 50 साल से निर्बाध रूप से चले आ रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को हेरान परेशान करने की गरज से उक्त रास्ते को बंद कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते मे बाउन्ड्रीवाल कर रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है। अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण द्वारा रास्ते को अवरुद्ध नही करने हेतु कहा गया तो उनके द्वारा साफ इंकार कर दिया गया। इसलि प्रार्थीगण को अपनी आराजी खसरा न0 153, 154, 155 ग्राम माधोपुरा मे आने जाने हेतु खसरा न0 152 के दक्षिण दिशा की ओर डोल के सहारे उत्तर से दक्षिण 10 फीट पूर्व से पश्चिम 50 फीट की सीमा तक नवीन रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकार्ड मे उसी अनुसार तरमीम की जावे। रास्ते के प्रयोजनार्थ काम आने वाली भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण देने को तैयार है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। धारा 251 ए के तहत आवेदन किया जाता है उस स्थिति मे उपखण्ड अधिकारी को संक्षिप्त जॉच के पश्चात यह समाधान करना होता है कि आवश्यकता अत्यधिक है नसेसिटी इज एक्सक्लूड नेसेसिटी है और यह जोत के केवल सुविधा जनक उपयोग के लिए नही है इसके अलावा अन्य खातेदार के जोत मे हेंजर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले पहुँचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तब आवेदन स्वीकार योग्य होने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। इस प्रकरण मे रेस्पो0/प्रार्थीगण ने चाहे गये स्थल पर हमेशा से रास्ता होना रास्ता 10 फीट चौडाई व 60 फीट लम्बाई का होना खसरा न0 152 व 153 के दक्षिण दिशा की डोल मेड पर होकर बताया है उसके बाद 153 की भूमि रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा खरीद करना बताया है। रेस्पो/प्रार्थीगण ने भूमि पर पहुँचने का यही एक मात्र रास्ता होना बताया है। जिसे प्रार्थीयान/रेस्पो0 बुजुर्गान के समय से पचासो साल से निर्बाध रूप से इल्म मे उपयोग करते चले आ रहे होना एवं आज भी कर रहे होना बताया है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि रेस्पो0 न0 1 ता 6 ने धारा 251 ए के तहत आवेदन किया है जबकि इन तथ्यो के आधार पर आवेदन न्यायालय उप जिला कलेक्टर मे विचाराधीन नही होता है बल्कि ऐसे तथ्यो के आधार पर आवेदन दीवानी न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होता है या धारा 251 आर टी एक्ट के तहत तहसीलदार के समक्ष ही विचारणीय होता है। इस स्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार विहित होने से निरस्त योग्य है। रेस्यो/प्रार्थीगण ने धारा 251 आर टी एक्ट के प्रावधान अनुसार अपने अभिवचन आवेदन में दर्ज नहीं किये। आवेदक रेस्यो0 ने आवेदन में यह भी दर्ज नहीं किया कि चाहे गये रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है और यह भी नहीं बताया कि चाहा गया रास्ता उसकी जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के नहीं है इस स्थिति से भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है। रेस्यो/प्रार्थीगण ने अपना आवेदन अपीलांटगण की जोते में होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामलो में वैकल्पिक मार्ग अभाव सिद्ध नहीं किया गया है इस प्रकार यह प्रथम तौर पर नये मार्ग का मामला आवेदकगण ने नहीं रखा है बल्कि आवेदन के पैरा न0 3 ता 5 में अपना प्रकरण सुखाधिकार अधिकार के तहत मेड डोल पर होकर रास्ता होना बताया है इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र आवेदकगण धारा 251 ए आर टी एक्ट के तहत विचारणीय नहीं है। बल्कि दीवानी न्यायालय द्वारा वाद के रूप में विचारणीय होता है। इस स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं व पत्रावली व रिकार्ड के विपरीत है मनमाना है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रावली पर आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन से दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि आवेदकगण को अपनी जोत में पहुँचने का अन्य खातेदार की जोत में होकर पहुँचने का वैकल्पिक साधन नहीं है जबकि मौके पर खसरा न0 160 व उसके अन्य मिन नम्बर जो आवादी के है जिनमें आवेदकगण व उनके परिवारजन निवास करते है वहाँ से खसरा न0 160/645 व खसरा न0 250/658 आम रास्ते से होकर खसरा न0 182 व 167 के मध्य होकर खसरा न0 168 में होते हुए खसरा न0 155 को रास्ता है वह रास्ता खसरा न0 250/658 से सी सी रोड खसरा न0 160/645 व खसरा न0 182 व 167 के मध्य होकर खसरा न0 168 तक बना हुआ है खसरा न0 168 के कुछ भाग में विधालय बना हुआ है उसके पहुँच के लिए एवं आवेदकगण की आराजी ख0न0 168 की पहुँच के लिए सीसी रोड बना हुआ है और खसरा न0 168 से बना हुआ आवेदकगण का खसरा न0 155 है। जो नक्शा शीट की छाया प्रति से प्रमाणित है। जिसमें वरंग लाल रंग डॉट लाईन से इस रास्ता को अपीलांट ने दर्शाया है इस रास्ता के अस्तित्व को आवेदकगण द्वारा छुपाया गया है और गिरदावर हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में छुपाया है। इस रास्ते का उपयोग आवेदकगण 30-40 साल से लगातार करते चले आ रहे है। इस प्रकार आवेदकगण को आवेदन दिवस न्यायालय हाजा में चाहे गये रास्ते की पहले से आवश्यकता नहीं रही है। और अपनी भूमि खसरा न0 155 के उपयोग के लिए अपील के इस पैरा में अपीलांट द्वारा बताया गया रास्ता आवेदकगण को सुविधाजनक उपयोग की है यह वैकल्पिक मार्ग आवेदकगण को उपलब्ध सीसी रोड बनाया गया है। गणपत सिंह पुत्र रामसिंह निःसंतान स्वर्गवासी हुए है आवेदकगण उनके हिस्से स्वामित्व खातेदारी की जमीन का आवेदक है व उपयोग करते चले आ रहे है और गणपत सिंह के वारिस है गणपत सिंह अविवाहित स्वर्गवासी हुए है। पटवारी हल्का मातासुला ने मौके पर रिपोर्ट बनाई जिसमें खसरा न0 154 व 155 में आवेदकगण के मकान बने होना बताया है और ग्राम की मुख्य आवादी से जगमोहन के घर से स्कूल तक ग्राम पंचायत द्वारा सी सी रोड का निर्माण किया हुआ होना बताया है यह सी सी रोड खसरा न0 154 व 155 की पहुँच के लिए सुविधाजनक है एवं खसरा न0 152 व 153 में मोहरम डली हुई होना नहीं बताया है। इस



राजस्व अपील प्राधिकारी

मिर्ठ

प्रकार पटवारी हल्का रिपोर्ट को तहसीलदार द्वारा छुपाया गया है। और बिना रिकार्ड के गिरदावर से असत्य रिपोर्ट मौके विपरीत पेश कर दी। गिरदावर रिपोर्ट पर आक्षेप प्रस्तुत करने का अवसर अपीलांट को नहीं दिया गया। गिरदावर द्वारा खसरा न0 155 मे आवेदकगण कृष्ण सिंह वगैरे के मकान होना बताया है भूमि खसरा न0 154 व 155 आवासीय उपयोग मे आती है। व भूमि कृषि जोत भूमि नहीं है इस स्थिति मे आवेदक बाबत धारा 251 ए आर टी एक्ट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं होने से क्षेत्राधिकार विहित आदेश पारित करने से यह आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदकगण द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य भी पेश नहीं किया है अपीलांट को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं दिया गया है और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह मात्र गिरदावर रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है। अपीलांट द्वारा वैकल्पिक रास्ता व सुविधाजनक रास्ता स्कूल की तरफ होकर खसरा न0 155 के लिए दर्शाया है उसके संबंध मे कोई विवेचन अपने निर्णय मे अधिनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिवत तौर पर जैर अपील निर्णय पारित नहीं किया है। रसपो0 आवेदकगण से ही धारा 251 ए आर टी एक्ट का मामला नहीं बनता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतया आरवेद्री एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.11.19 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रसपो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत ही जैर अपील निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन विधि विरुद्ध है कि प्रार्थीगण/रसपो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर टी एक्ट के तहत लागू नहीं होता है जबकि राज्य सरकार द्वारा किसी जोत धारक की भूमि पर पहुँच मार्ग न होने तथा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की स्थिति मे धारा 251 ए लागू की गई है। रसपो0/प्रार्थीगण को अपनी जोत पर पहुँच का मार्ग खसरा न0 135 गैर मुमकिन रास्ते से खसरा न0 152 व 153 से होकर वर्षों से आवागमन करते रहना एवं अपीलांटगण/अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को अवरुद्ध किये जाने के कारण ही विधिवत रूप से धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पर अपीलांट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलांट/अप्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट पर सुना जाकर ही निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को सही एवं वास्तविक स्थिति अनुसार ही पेश की गई है जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत माना है। मौका रिपोर्ट मे रसपो0/प्रार्थीगण की जोत पर पहुँच के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होना माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से रास्ते के लिए उपयोग मे काम आने वाली भूमि की डी एल सी दर की दो गुना राशि अप्रार्थीगण/अपीलांट को दिये जाने की शर्त पर राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड, मौका रिपोर्ट एवं उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर ही विधिवत रूप से निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधित त्रुटि नहीं है।

अतः अपीलांत की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिसमें यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पोंडेंट द्वारा आराजीयात खसरा नं० 153,154,155 पर पहुँच हेतु पूर्व से कोई रास्ता नहीं होना तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने तथा पूर्व से आमद रफ्त का रास्ता आराजी खसरा नं० 135 सिवायचक गैर मुमकिन रास्ते से होकर रहने तथा अपीलांत/अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं० 152 को अपीलांत/अप्रार्थीगण द्वारा अवरुद्ध किये जाने के कारण ही धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था। अपीलांत अधिवक्ता का कथन रहा कि प्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट को रास्ता हेतु सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ता प्रदान किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। इसी प्रकार अपीलांत अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया गया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर उभयपक्ष की सहमति पर मौके पर पीठासीन अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने की सहमति दी जाने पर स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर ही मौके की रिपोर्ट तैयार कराई गई है। मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट की आराजीयात पर पहुँच का रास्ता पूर्व से मौजूद नहीं होने एवं सबसे निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता आवागमन हेतु अपीलांत के खेत खसरा नं० 152 में 12 फीट चौड़ा व 24 मीटर लम्बा रास्ते की भूमि प्रभावित भूमि की डी एल सी दर की दो गुना राशि अपीलांत /अप्रार्थीगण 1 ता 5 को दिलियावे जाने की शर्त पर स्वयं प्रार्थी/रेस्पोंडेंट की आराजी खसरा नं० 153 में 12 फीट चौड़ा व 30 मीटर लम्बाई की भूमि तथा खसरा नं० 154 में 12 फीट चौड़ा व 30 मीटर लम्बा एवं खसरा नं० 155 में 12 फीट चौड़ा व 58 मीटर लम्बाई की भूमि प्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट के हिस्से की खातेदारी भूमि में से खातेदारी कम कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश विधिवत रूप से धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत ही दिये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांत की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांत खारिज योग्य होन से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर रोडाभोम के प्रकरण संख्या 05/19 में पारित निर्णय दिनांक 6.11.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को लिखाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपीलांत प्रविधिकारी
सवाई माधोपुर